

प्रेषक,

आरक्षणीनासी सुन्दरम,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,

सहकारी समितियाँ,

उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

सहकारिता, गन्ना एवं बीनी अनुभाग-1

देहरादून

दिनांक 25, मई, 2017

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में पैक्स मिनी बैकों में जमा निक्षेप हेतु निक्षेप गारन्टी योजना (कॉरपस फण्ड) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के आदेश संख्या-312/3(150)/XXV(1)/2017 दिनांक 31 मार्च 2017 के क्रम में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त निर्यात करने विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या-865/नियो0/कारपस फण्ड/2017-18 दिनांक 02 मई 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारिता विभाग के अन्तर्गत पैक्स मिनी बैकों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना (कॉरपस फण्ड) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि रु0 13,33,000/- (रुपये तीस लाख तीस हजार मात्र) निम्नांकित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की भी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) योजना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:-6838-43/40प्र0वि0/सह0/2003-04 दिनांक 17 मार्च 2004 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना नियमावली, 2004 की शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (2) योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार का अदान 0.30 प्रतिशत की दर से (गत वर्ष निक्षेप राशि में हुई वृद्धि पर) अनुमत्त होगा। प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति, जिला सहकारी बैंक एवं शीर्ष बैंक के अदान जो कि क्रमशः 0.15, 0.10 एवं 0.05 प्रतिशत (गत वर्ष निक्षेप राशि में हुई वृद्धि पर) है, तत्काल जमा किये जाए। योजना का अनुश्रवण दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित किया जाय तथा उसकी प्रगति से शासन को भी नियमित रूप से अवगत कराया जाए।
- (3) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नहीं है यदि

(2)

सुसमाप्त नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(6) चालू वर्ष 2017-18 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या-312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च 2017 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा चालू वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य समयबद्ध आधार पर प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए।

2. उक्त व्यव चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता-राजस्व-00-107-क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता-02-पैक्स मिनो बैंको में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना-00-20-सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता के नामे खर्चा जायेगा।

3. उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च 2017 द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा निर्देशों के कम में जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(आर०मी०नासी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या-486(1)/XIV-1/2017, तद्विनांकित।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त-4/नियोजन/माषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमायू/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
6. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।